ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, **AKBAR ROAD, NEW DELHI**
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **29 December, 2020**

Shri Rajeev Shukla, In-Charge Himachal Pradesh, AICC and Shri Govind Singh Dotasra, PCC President, Rajasthan addressed media at AICC Hdqrs., today.

श्री राजीव शुक्ला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि ऐसी ठंड में आप लोग मौजूद हैं, वैसे ही मौजूद हैं जैसे पूरी रात संघर्ष करके किसान वहाँ ठंड मे बैठे हैं बॉर्डर पर, लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा है। यहाँ सरकार रजाईयों की गरमाहट में हैं, आनन्द ले रहे हैं मंत्री, अपना बैठे हुए हैं, वहाँ किसान ठंड में परेशान हैं, उनके प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए वो सहानुभूति सरकार की नहीं है।

इस प्रेस कांफ्रेंस का आज जो मकसद है, कल सरकार की वार्ता किसानों से होने जा रही है ऐसा सरकार ने कहा है, लेकिन आज सुबह मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री का इंटरव्यू देख रहा था। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने एक भी जगह ये कमिटमेंट नहीं दिया है कि वो कानून में कोई संशोधन करेंगे, या कानून वापस लेंगे या किसानों की जो बात है, उसे कानून में शामिल करेंगे। सरकार की यही एक ट्रिक है कि ये आश्वासन देते हैं, मौखिक सब कहते हैं और सरकार के स्तर पर कानूनी रुप से लिख कर देने को तैयार नहीं हैं। इसमें टैक्निकल चीजें वो हुई हैं कि ये कानून में शामिल करने से बच रहे हैं, क्योंकि कानून में शामिल करने का मतलब बिल का हिस्सा उन बातों को बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा, जिससे ये बच रहे हैं।

इनका है कि सिर्फ आज लिखकर सरकार दे दे जिसकी कोई वैल्यू नहीं बाद में, एक सरकार ने लिख दिया, दूसरी सरकार उस कैबिनेट के डिसीजन को उलट देती है या तीसरी सरकार उसको नहीं मानेगी और आगे कोई अफसर नहीं मानेगा इसलिए इनकी टैक्नीकल चीज जो है अवॉइड कर रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, मंडियाँ कहीं नहीं जाएंगी, हमारा वचन है, हमारा वादा है। लेकिन ये वादे कुछ नहीं, वचन का कोई अर्थ नहीं होता जब तक वो कानून का हिस्सा नहीं बनता, ये कानून नहीं बनाना चाहते, इसमें सिर्फ तकनीकी दृष्टि की बात है। तो कल की जो वार्ता में भी अगर वो बात इसको कानून में शामिल करने की बात रहेगी। बड़ी सिंपल सी बात है कि एमएसपी कंटिन्यू करेंगे, मंडियाँ उसी तरह चलती रहेंगी और कोई भी प्राईवेट प्लेयर से अगर आप इसको रीफॉर्म करते हैं तो कोई भी प्राईवेट प्लेयर, कॉर्पोरेट वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता, इतनी बात ही तो कानून में देनी है आपको, वो कानून का हिस्सा ही बनाने को तैयार नहीं हैं और उसको घुमा-घुमाकर वार्ता को बढ़ाते जा रहे हैं, पर ये बात करने को तैयार नहीं। तो हमारी मांग है कि जो भी आप करें, जो भी उनके साथ समझौता हो अगर किसान तैयार हैं, उनकी शर्तें आप मानते हो, तो कानून का हिस्सा

होना चाहिए यही किसान मांग करते हैं, यही हम सबकी मांग है कि आप किसानों की मांग मानें।

दूसरी बात ये है कि एक जो बार-बार बात कही जाती है कि एक तो डेढ प्रदेश का आंदोलन है, पंजाब और आधा हरियाणा, ये इनकी गलतफहमी है, वहाँ भी यदि आप जायें, यूपी बॉर्डर पर जो बैठे हुए हैं, वो क्या पंजाब और हरियाणा के हैं? वहाँ पर जाइए आपको मध्य प्रदेश का किसान मिलेगा, वहाँ राजस्थान का किसान मिलेगा, वहाँ महाराष्ट्र का किसान मिलेगा, आज तो हमारे सहयोगी दल हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा कि वो किसान आंदोलन को, महाराष्ट्र तो जाना ही जाता है किसानों के लिए, वहाँ के बड़े प्रगतिशील किसान हैं, कॉपरेटिव, अगर कॉपरेटिव का सबसे बडा सहकारिता का कोई प्रयोग है तो महाराष्ट्र में हुआ है, जहाँ पर वो कर रहे हैं, इनके लोग भी दक्षिण भारत के लोग बराबर आ रहे हैं और मैंने भी सुना है कि जो किसान धरने पर बैठते हैं, फिर जाते हैं उसी गांव से दूसरे गांव के किसान भी आ जाते हैं तो इस तरह से पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अब दक्षिण बगैरह के लोग कम हो गए क्योंकि दूर से आना जाना होता है, लेकिन उनकी बात यहाँ के लोग बुलंद कर रहे हैं और उसमें कोई इसको जो ट्विस्ट देते हैं बार-बार कि ये राजनीतिक दलों का आंदोलन है, झोलाछाप लोगों का आंदोलन, ये सब लोग जो हैं जानबूझकर आंदोलन को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, किसान इसको चला रहे हैं, वरना इतनी भारी संख्या में, इतनी ठंड में कितनी भी आप लगा लीजिए उनको दूध मिल रहा है और उनको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है खाने को, आप बैठ जाइए न जाकर, आपको दूध तो क्या आपको तो आईसक्रीम और रसमलाई सब देंगे, बैठोगे आप खुले में, वहाँ पर, रात में। तो ये जो है इनका जो है कहने को है, इससे किसानों को बदनाम करने की चेष्टा है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि किसानों से वार्ता करें, उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखें और वार्ता में जो उनकी मांग है, वो पार्लियामेंट से पारित कानून का हिस्सा होनी चाहिए। It has to be included, inserted into the bill, which Parliament should pass, that much Government should do, this is what I want to say.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा – जब मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए थे एनडीए की तरफ से, तब मोदी जी ने किसानों से दो वादे किए थे।

एक वादा किया था कि किसान की आमदनी को दोगुना करूँगा।

दूसरा वादा किया था कि किसान की जो उपज है, उसके ऊपर जो लागत आती है, उसके ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत मैं मुनाफा दूँगा और किसान ने दिल खोलकर मोदी जी को वोट दिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को गरीब बताते हुए वोट लिए थे और किसानों ने वोट दिए थे पर ज्यों ही एनडीए प्रथम में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने सबसे पहले यूपीए के समय सर्वसम्मति से पास किए गए भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमे भाजपा भी शामिल थी, जिसके वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने किसानों का जो भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए सरकार के समय बना था, अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ देने के लिए उसमें संशोधन करना चाहा और देश के किसानों ने हुंकार भरी मोदी जी के खिलाफ, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी हुई और आपने देखा होगा कि मोदी जी को मुंह की

खानी पड़ी उन संशोधनों को वो नहीं कर पाए, जो अपने उद्योगपति मित्रों के लिए करना चाहते थे।

जब एनडीए-2 बनी तो मोदी जी ने एक बार फिर उस किसान के ऊपर, जिसके वोट से वो दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने दूसरी बार किसान के ऊपर हमला किया। आपने देखा वो तीन काले कानून, जिनके खिलाफ आज 34 दिन से किसान ठंड में, पाले में, सड़क के ऊपर अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे सोकर विरोध कर रहा है। इन तीन काले कानूनों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी लोकसभा में, हमारी राज्यसभा में, किसी भी प्रदेश की, किसी भी स्टेट की विधानसभा में या विधान परिषद में किसी भी नेता ने, किसी भी पॉलीटिकल पार्टी ने और किसी भी किसान संगठन ने कभी भी इन तीन काले कानूनों की मांग नहीं की थी, तो मोदी जी, ये आपने फिर किसके कहने से, किसकी आवश्यकता के लिए ये तीन काले कानून बनाए, जरा बताने का कष्ट करें, लेकिन आज तक मोदी जी वो बात नहीं बता पा रहे हैं।

इन तीनों काले कानूनों के आधार पर किसान का समर्थन मूल्य खत्म करना चाहते हैं। एपीएमसी की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं और जो किसान की उपज है, जिसके आधार पर वो अपना भी पेट पालता है और पूरे देश के लोगों का पेट पालता है, उसके ऊपर अपने उद्योगपति मित्रों का कब्जा कराने का ये षड़यंत्र मोदी जी ने किया और इसलिए पूरे देश के किसान आज उनके खिलाफ आंदोलनरत हैं।

राजस्थान में किसान आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इन तीनों काले कानूनों का जो नुकसान हमारे किसानों को नहीं हो, इसलिए राजस्थान की विधानसभा में कानून पारित किए। आज दो महीने के लगभग होने को हैं, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय उन कानूनों को आगे महामहिम राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहे हैं। अगर वो कानून गलत होंगे तो राष्ट्रपति जी को भेजने में उनको क्या दिक्कत आ रही है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ में खड़ी है और जिस प्रकार से जो यहाँ पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठंड में बैठे हैं, उन किसानों के साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाल रही है, संघर्ष यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस संवाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन मोदी जी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। मोदी जी के जो मित्र हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, वो जैसे बिल्ली को देखकर चूहों में अफरा-तफरी और भागने का माहौल होता है, वो माहौल हो रहा है, लेकिन फिर भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये वो मोदी जी हैं, जो अपने आप को कहते थे कि मैं फकीर हूँ, झोला उठाकर चला जाऊँगा, वो मोदी जी आज किसान को वोट तो फकीर बताकर ले लिया, लेकिन उद्योगपति मित्रों के वजीर बनकर बैठे हैं, देश के किसानों के वजीर वो नहीं रहे।

आज मोदी जी 30 किलोमीटर पर जाकर किसान से बात नहीं कर सकते, लेकिन मन की बात करने के लिए समय है। प्रायोजित रुप से भाजपा के वर्कर के साथ में किसान बनाकर के उनके साथ संवाद करने के लिए उनके पास समय है, लेकिन जो किसान 34 दिन से भूख से तड़प रहा है, ठंड में बैठा है, उनसे बात करने के लिए मोदी जी के पास में समय नहीं है। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किसानों के साथ हर दम खड़ी है, जब तक किसान की मांग को ये केन्द्र की, मोदी जी की सरकार नहीं मानेगी, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस आंदोलन में किसान का साथ नहीं

छोड़ने वाला है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में किसान तीन कृषि कानूनों से परेशान है, भाजपा द्वारा किसी तरीके से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो प्रमुख विपक्षी दल है राजस्थान में, भाजपा, 25 में से 25 सांसद प्रदेश की जनता ने उनको दिए 3 - 3, 4 - 4 मंत्री भी केन्द्र के अंदर बने, लेकिन एक भी रुपया केन्द्र से नहीं ले गए और न किसानों की आवाज बन रहे हैं, बल्कि किसानों के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और 8-8 चेहरे अपने आपको मुख्यमंत्री बनाकर मुख्यमंत्री-मुख्यमंत्री खेल रहे हैं, प्रजातांत्रिक रुप से चुनी हुई सरकार गिराने का षड़यंत्र कर रहे हैं, लेकिन किसानों की आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी जी अब भी समय है आपके पास में, जिस किसान के वोट के दम पर आप जीतकर आए हो, उसके लिए आप काम कीजिए, अपने बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए काम मत कीजिए।

पहली बार देश के इतिहास में अगर किसी उद्योगपति ने किसान के खिलाफ विज्ञापन देकर ये बताया कि मैं किसान की उपज खरीदने वाला नहीं हूँ, मैं तो केवल मेरे गोदाम बना रहा हूँ, आधुनिक गोदाम। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, पूछिए उद्योगपति अपने मित्रों से कि जब आपको किसान की उपज खरीदनी नहीं है तो आप ये हाई टैक्नीक वाले बड़े-बड़े जो गोदाम बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं, क्या रखेंगे?

आज देश की जनता जान चुकी है मोदी जी को कि वो तेल, रेल, एलआईसी और अब पूंजीपति उद्योग मित्रों को सौंपने की बारी किसान की उपज है, जिससे किसान, किसान न रहकर वो मजदूर बन जाए, ये तानाशाही रवैया हमारी देश के प्रधानमंत्री जी का और मोदी जी की सरकार का है। इसके खिलाफ़ पूरे देश में और राजस्थान प्रदेश में पूरी तरह से आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। राहुल गांधी जी ने जब हुंकार भरी थी तो भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन नहीं हुआ था। आज भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारा राजस्थान प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो, वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता किसान के लिए खड़ा है। उसका दिन और रात कभी भी हो, उसका साथ देने के लिए तैयार है।

ये जो चीजें हैं, वो पूरे देश की जनता जान चुकी है कि मोदी जी एक दिन भी मीडिया से रूबरू होकर अगर आपका सवाल ले लें, तो आप हमे बता देना कि आज हमारा सवाल ले लिया। वन वे ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक नहीं है। केवल वोट लेने के लिए टू वे है, जिस दिन वोट लेना हो, मोदी जी वोट लेते हैं, उसके बाद वन वे चलता है। कभी भी संवाद वो न मीडिया से करेंगे, न किसान से करेंगे, मन की बात कहते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। मन बेईमान हो सकता है, लेकिन काम के लिए प्रधानमंत्री चुना था, न कि केवल मन की बात करने के लिए और न इस तरह के प्रपोगैंडा करके अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए।

धन्यवाद।

किसानों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में श्री शुक्ला ने कहा कि हम तो किसानों के साथ हैं, लेकिन पहली बार एमएसपी को खत्म करने की साजिश हो रही है, हम लोगों ने कभी साजिश नहीं की। हमने एमएसपी बढ़ाई, हमने किसानों की मदद की, हमने उनके कर्ज माफ किए। वो जो पार्टी अध्यक्ष हमसे कहते थे कि राहुल गांधी जी ने किसानों के लिए क्या किया- अरे हमने तो सबसे पहले शुरुआत की। हमने तो उनके करीब 80 हजार करोड़ के किसानों के कर्ज माफ

किए, किसानों के लिए नहीं किया तो किसके लिए किया? मनरेगा कौन लाया? उसका भी फायदा गांव के मजदूरों, किसानों को मिलता है, ये सारे काम तो कांग्रेस ने किए हैं और आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ किया ही नहीं जब उनकी सरकार थी- तो आप भूल गए? नेहरू जी और सरदार पटेल जी के काम तो आप बता रहे हो, जब थे ही नहीं आप और जो सामने अभी काम हुए पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह सरकार में उन कामों को भूल गए आप, तो ये सारे किसानों के लिए ही तो काम किए हैं। यहाँ पर तो एमएसपी खत्म करने की जो साजिश है, वो किसान की समझ में आ गई कि हाँ कोई शंका हो रही है उन कानूनों में।

इसी से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री शुक्ला ने कहा कि वहीं तो मैं कह रहा हूँ, कि उतना ही कानून में डाल दो जो कह रहे हो। जो मौखिक आप आश्वासन दे रहे हो, उसको पार्लियामेंट से पास करा दो, बस। इतनी सी बात है, आप भी नहीं समझ पा रहे हो।

On a question about supporting farmers' agitation, Shri Shukla said- We are supporting Kisan agitation. We are supporting farmers' agitation, because they are raising a genuine demand and we are all with that demand. UPA Government also helped the farmers. We have never tried to unnecessary subvert these laws, but, these people, their motives are altogether very dubious that way. They want to really harm the farmers, so keeping that in mind, if the talks fail, because today there was a statement by the Agriculture Minister, he was candid and clear that we will talk about provisions and all that, but, he has not given any commitment with that the Government is going to bring the fresh laws incorporating those amendments which farmers are suggesting, so that means he is not going to do that, so, there is every possibility talks may fail, talks may work, if the Government consider and they are sympathetic to the farmers, they should accept those suggestions and should repeal the laws and bring another bill in Parliament, but, if it doesn't happen, Mr. Sharad Pawar has been a former Agriculture Minister, and Maharashtra has always, you know, raised the issues of farmers, so our sympathy and support is with the farmers. Opposition parties are not directly involved, but, definitely they are trying to help farmers and It is our duty, it is our job to help farmers of the country, the poor of the country, the workers of the country, so, there is no harm if political parties, they extend their support to these kind of agitations.

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की रणनीति यही है कि हमारा उस आंदोलन के साथ पूरी सहानुभूति है हम उस आंदोलन का समर्थन करते हैं और किसानों की मांग जायज है, बराबर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि किसानों की जायज मांग को स्वीकार करे और सिर्फ मौखिक आश्वासन से, भाषणों में आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इसको कानूनी जामा पहनाएं, यही कांग्रेस की मांग है।

बढ़ती बेरोजगारी और अकेले नवम्बर माह में 35 लाख लोगों की नौकरी छिन जाने के बारे में पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री शुक्ला ने कहा कि हम लोगों के हिसाब से जो पिछली बार हमने आंकड़ा दिया था चुनाव में, साढ़े चार करोड़ लोग जो हैं, उनका कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में उनकी नौकरियाँ गईं और अब ये आंकडा 4 करोड़ और 85 लाख से ज्यादा हो गया है। लगातार तमाम उद्योग - धंधे, व्यापार, ये सब खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने जिस तरह से नोटबंदी लागू की, जीएसटी लागू की और उसके बाद से लगातार लॉकडाउन को जिस ढंग से सरकार ने हैंडिल किया, उससे तमाम लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, यूथ परेशान है, कौन खुश है? अच्छे दिन! किस चीज के अच्छे दिन? यूथ अलग परेशान है, लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, किसान परेशान है, सड़कों पर पड़ा है, आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, कौन खुश है, कौन सा वर्ग खुश है बताओ न। छोटे-छोटे दुकानदार परेशान हैं। जिसको देखो, वही कहता है, यार, बड़ा गड़बड़ चल रहा है। आप जाकर, बैठकर खुद बात करके देख लो। चाहे पान वाला हो, चाहे मूँगफली का ठेला लगाने वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, तो सब जब परेशान हैं, जब ये नौकरियाँ लोगों की धड़ाधड़ जा रही हैं, तो ये तो सोचना पड़ेगा सरकार को। आप अगर डिनायल मोड में बैठे रहोगे, आप ये मानोगे नहीं कि सब गलत कहते हैं, जो ये बोल रहा है, सब विपक्षी दलों की साजिश है, सब ये पाकिस्तानी के कहने पर हो रहा है, सब ये चीन के कहने पर हो रहा है, सब ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ बोल रही है, सब यही सोचकर बैठे रहोगे, तो आप कुछ सुधार ही नहीं कर पाओगे। अगर जो गलती मानकर सुधारे, वही सबसे अच्छा आदमी कहा जाता है। जब आप गलती मानने को तैयार ही नहीं हो, जब ये मानने को तैयार नहीं कि कुछ गड़बड़ है, सब सही चल रहा है, तो फिर कहाँ से सुधारोगे, ये समस्या है।

राजस्थान के किसानों से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि आपने सही कहा कि राजस्थान के किसान इन तीनों काले कानूनों से पीड़ित हैं, परेशान हैं, आक्रोशित हैं। लाखों बॉर्डर पर बैठे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के स्थापना दिवस, 28 तारीख से किसान संवाद कार्यक्रम चालू कर रखा है। सेवादल ने किसान यात्रा चालू कर रखी है और तमाम किसान अब दिल्ली को घेरने की तैयारी में हैं, राजस्थान से तकरीबन-तकरीबन किसान देख रहे हैं, कल की वार्ता अगर बेनतीजा रही, तो वो किसान पूरे बॉर्डर पर आकर दिल्ली को घेरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि किसान की जो लिमिट है, वो क्रॉस हो चुकी है, मोदी जी के प्रति इतना भयंकर आक्रोश है कि जिसको हमने दो बार देश का प्रधानमंत्री बनाया, उसके कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है, हमारे यहाँ पड़ाव के बावजूद। तो कांग्रेस पार्टी किसान के साथ में खड़ी है, निश्चित रुप से।

एक अन्य प्रश्न पर कि इंग्लैंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप व नए स्ट्रेन के समाचारों के बीच क्या इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भारत आना चाहिए के उत्तर में श्री शुक्ला ने कहा कि जिस दिन ये आया था कि कोरोना दोबारा से इंग्लैंड में बढ़ रहा है और सारे यूरोपियन देशों ने अपनी फ्लाइट बंद की थी, उसी दिन भी हमने ट्वीट करके ये मांग की थी कि तत्काल भारत को प्रिकॉशनरी स्टेप लेने चाहिए और इस तरह के लोगों का आना जाना रुकना चाहिए, फ्लाइट्स पर नियंत्रण करना चाहिए। ये हमारी मांग है कि वो अभी तक नहीं किया गया, तत्काल वो करना चाहिए। पिछली बार भी यही चूक हुई थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। अभी तो एक ही

डेस्टिनेशन से रोकना है, वो तो आसानी से किया जा सकता है, तो वो उनको करना चाहिए, वो अभी तक नहीं किया, क्या कारण है वो अभी तक मेरी समझ में नहीं आता।

जहाँ तक बोरिस जॉनसन जी के आने का सवाल है, इस मामले में आपको पता है कि विदेश नीति, चाहे कोई भी सरकार आए, सेम रहती है, अगर उनको अतिथि बनाया गया है तो हम उनका स्वागत करते हैं। प्रिकॉशन सरकार को पूरे लेने चाहिए, लेकिन किसी के आतिथ्य में हम कोई भी सवाल नहीं उठाते हैं और स्वागत है हमारे विदेशी अतिथि का।

उत्तर प्रदेश से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सार्थक भूमिका कांग्रेस निभा रही है और लगातार कांग्रेस वहाँ आंदोलनरत है, लेकिन ये नया रवैया उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है कि न केवल कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस नेता कोई जरा भी विरोध करे, उसको जेल में डाल देते हैं, पत्रकारों को भी जेल में डाल देते हैं, पत्रकारों के ऊपर भी केस कर देते हैं। अब नया तरीका चालू हुआ है कि विरोध में तो आप कुछ बोलिए ही मत, या तो हमारी प्रशंसा करिए और प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आपने विरोध में बोला कि आपके खिलाफ केस किया, ये बड़ी एक विचित्र स्थिति वहाँ पर हो गई, तो उस चक्कर में कांग्रेस के नेता लगातार बंद किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। लगातार हमारे अध्यक्ष, और सारे लोग जेल जा रहे हैं और लोग भी लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, इससे न झुकने वाले हैं और न इससे पीछे हटने वाले हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम की हम कड़ी निंदा करते हैं कि जिसमें विरोध को सुनना नहीं चाहते हैं और लोकतंत्र की बात भी करते हैं।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC